

ख़ास-ख़बरेँ

आशुतोष दीक्षित ने संभाली कमान

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: एयर चीफ मार्शल आशुतोष दीक्षित ने शनिवार को भारतीय वायु सेना के 29वें प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया। उन्होंने एयर चीफ मार्शल एपी सिंह का स्थान लिया, जो 42 वर्षों की विशिष्ट सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुए। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र आशुतोष दीक्षित को 6 दिसंबर 1986 को वायु सेना की लड़ाकू विमान शाखा में नियुक्त किया गया था। चार दशक के सेवाकाल में उन्होंने सैन्य अभियानों, उड़ान परीक्षण और रक्षा क्षमताओं के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्हें मिराज-2000, मिग, जयुआर सहित विभिन्न विमानों को उड़ाने का 3,300 घंटे से अधिक अनुभव है। उन्होंने उप वायु सेना प्रमुख और एकीकृत रक्षा स्टटाफ प्रमुख सहित कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया।

आजम खान को ईडी ने गिरफ्तार किया

नईदुनिया ब्यूरो, रामपुर: समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान 11 महीने बाद बेटे अब्दुल्ला के साथ रामपुर जेल से बाहर आए, लेकिन जेल के द्वार पर ही प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद अधिकारी उन्हें अपने साथ ले गए। उन्हें गाजियबाद न्यायालय में पेश किया जाएगा। ईडी जीहर विश्वविद्यालय के निर्माण में सरकारी धन और ठेकों से जुड़े पैसें के दुरुपयोग के आरोपों की जांच कर रही है। एजेंसी 416.14 करोड़ रुपये के खर्च में अनियमितताओं और धनशोधन की जांच कर रही है।

केशम द्वीप के पास हमले का आरोप

तेहरान, एजेंसी: ईरान ने आरोप लगाया है कि अमेरिका ने केशम द्वीप के पास हमला किया। ईरान के दावे के अनुसार, हमले में मछली पकड़ने वाली नौकाओं को निशाना बनाया गया। इस घटनाक्रम के बीच ईरान के सर्वोच्च नेता मौजतबा खामेनेई ने कहा कि अब युद्ध कब और कैसे समाप्त होगा, यह ईरान तय करेगा। ईरान की ओर से अमेरिकी हमले को लेकर आरोप लगाए गए हैं। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में हमले के संबंध में अमेरिका की प्रतिक्रिया का उल्लेख नहीं है। घटना के विवरण और नुकसान को लेकर भी कोई विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। मौजतबा खामेनेई ने युद्ध की समाप्ति को लेकर ईरान के निर्णय का संकेत दिया। उनके बयान के अनुसार, युद्ध कब और किस तरीके से समाप्त होगा, इसका फैसला ईरान करेगा।

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने निधि राजदान से की शादी



नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पूर्व पत्रकार निधि राजदान से शादी कर ली है। उमर ने शनिवार को सामाजिक माध्यम पर दोनों की तस्वीरें साझा करते हुए लिखा, 'कल एक नई शुरुआत हुई, 'निधि' उनकी पोस्ट के साथ अंगूठी का संकेत भी था। निधि राजदान ने भी अपनी पोस्ट में अंगूठी का संकेत साझा करते हुए विवाह की पुष्टि की। दोनों की तस्वीरें सामने आने के बाद सामाजिक माध्यम पर चर्चा शुरू हो गई। उमर अब्दुल्ला का पहली पत्नी पायल से 31 जुलाई को सर्वोच्च न्यायालय ने आपसी सहमति से तलाक मंजूर किया था। दोनों की शादी 32 वर्ष पहले हुई थी और वे 2011 से अलग रह रहे थे।

उमर के खिलाफ 24 विधायक

नईदुनिया ब्यूरो, श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के भीतर मंत्रिमंडल विस्तार के बाद असंतोष बढ़ गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के खिलाफ पार्टी के 24 विधायक एकजुट हो गए हैं। शुक्रवार को 18 विधायकों ने श्रीनगर में लीलाब के विधायक केसर जमशेद लोन के आवास पर बैठक की, जबकि छह विधायक वीडियो संवाद के माध्यम से शामिल हुए। विधायकों ने मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर सोगामी और 27 अक्टूबर को मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल किए गए चार नए मंत्रियों को हटाने की मांग की है। इसके साथ ही मंत्रिमंडल में बड़े बदलाव की मांग उठाई गई है। नासिर सोगामी पर पार्टी नेतृत्व को गुमराह करने और संगठन के कामकाज में हस्तक्षेप करने के आरोप लगाए गए हैं। असंतुष्ट विधायक अब पार्टी अध्यक्ष फारुक अब्दुल्ला से मुलाकात कर अपनी मांगें रखेंगे।

नईदुनिया ब्यूरो, अहमदाबाद: प्रधानमंत्री रेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि देश का दुर्भाग्य है कि विपक्ष विरोध करने के बजाय अवरोध की राजनीति पर उतर आया है। विपक्षी नेता देश को बांटने की साजिश में लगे हैं। उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा कि विदेश में कौन किससे गुपचुप मुलाकात कर रहा है, यह सब दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से एकजुट रहने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री गुजरात के एकता नगर (केवडिया) में सरदार वल्लभभाई पटेल की 151वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने 'स्टेच्यू ऑफ यूनिटी' पर लोगों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि नक्सलवाद समाप्त हो गया है, लेकिन वैचारिक नक्सलियों का खतरा अभी बरकरार है। सामाजिक माध्यमों को हथियार बनाकर देश के खिलाफ इस्तेमाल करने की साजिश रहे रही है। इससे निपटने की आवश्यकता है।



उन्होंने कहा कि वर्तमान समय बीते कई दशकों के सबसे कठिन समय में से एक है। कई देशों में युद्ध चल रहे हैं। संसाधनों का संकट बढ़ रहा है और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बिखर रही है। ऐसे कठिन समय से निकलने के लिए देश की एकता बनाए रखना आवश्यक है। प्रधानमंत्री ने शांति स्थापित करने के लिए बलिदान देने वाले जवानों को नमन करते हुए कहा कि आज भारत पहले से अधिक सुरक्षित है। उन्होंने कहा

कि किसी भी देश के लिए वह अपने भविष्य का निर्णय स्वयं स्वतंत्रता जरूरी है, क्योंकि इससे करता है।

दिल्ली से वाराणसी साढ़े तीन घंटे में पहुंचाएगी बुलेट ट्रेन

वाराणसी: दिल्ली से वाराणसी तक बुलेट ट्रेन चलाने की योजना को मंजूरी मिल गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को वाराणसी में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली-वाराणसी-गुवाहाटी बुलेट ट्रेन के उतरवर्ती गलियारे को स्वीकृति दी है। इस मार्ग पर नई दिल्ली से आगरा की यात्रा लगभग एक घंटे में और वाराणसी तक का सफर साढ़े तीन घंटे में पूरा होगा। गलियारा दिल्ली से शुरू होकर आगरा, कानपुर, लखनऊ और अयोध्या होते हुए वाराणसी पहुंचेगा। इसके बाद पटना, सिलीगुड़ी और गुवाहाटी तक विस्तार होगा। दिल्ली से वाराणसी की दूरी लगभग 807 किलोमीटर है। वर्तमान में तेजस और राजधानी जैसी रेलगाड़ियों से यह यात्रा पूरी करने में दस घंटे से अधिक समय लगता है।

मंत्री हरदीप पुरी ने राज्यसभा उपचुनाव के लिए भरा नामांकन



नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शनिवार को मध्य प्रदेश से राज्यसभा उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उन्होंने अपनी और पत्नी की संपत्ति तथा आय का विवरण हलफनामे में प्रस्तुत किया। हलफनामे के अनुसार, वर्ष 2021-22 में उनकी पत्नी की वार्षिक आय 15.39 लाख रुपये थी, जो 2025-26 में बढ़कर 1.69 करोड़ रुपये हो गई। बड़का पुरी ने हरदीप पुरी की वार्षिक आय 63.26 लाख रुपये से बढ़कर 75.57 लाख रुपये दर्ज की गई। पत्नी के नाम 10.66 करोड़ रुपये की चल संपत्ति और 2,90,658 अमेरिकी डॉलर हैं। वहीं, हरदीप पुरी के नाम 6.54

करोड़ रुपये की चल संपत्ति दर्ज है। अचल संपत्ति के विवरण में पत्नी के नाम नौ करोड़ रुपये की संपत्ति और 30 लाख स्विस फ्रैंक की संपत्ति का उल्लेख है। हरदीप पुरी के नाम 20 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति दर्ज है। हरदीप पुरी ने आय के स्रोतों में पेंशन, केंद्रीय मंत्री का वेतन, दिल्ली स्थित संपत्ति से किराया और बैंक जमा पर ब्याज बताया है। उनकी पत्नी की आय में भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र से मिलने वाली पेंशन, जिनेवा स्थित संपत्ति का किराया तथा बैंक ब्याज शामिल हैं। नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। मंत्री कृष्णा गौर उनकी प्रस्तावक बनीं।

2024 का लोकसभा चुनाव अवैध: राहुल

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 2024 के लोकसभा चुनाव को अवैध बताते हुए दावा किया कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के माध्यम से 13.3 करोड़ यानी 15 प्रतिशत मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए गए। इनमें से कई मतदाताओं ने 2024 के लोकसभा चुनाव में मतदान किया था। उन्होंने कहा कि उस चुनाव में जीत का अंतर केवल तीन प्रतिशत मतों का था। राहुल गांधी शनिवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर आयोजित विपक्ष की मॉक संसद की संबोधित कर रहे थे। उन्होंने करीब 15 मिनट तक अपनी बात रखी। इस मॉक संसद की अध्यक्षता पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने की। विपक्ष की यह संसद तीन घंटे 23 मिनट तक चली। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जनमहाभियोग प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव में उन पर छह आरोप लगाए गए। सभी सांसदों ने प्रस्ताव को पारित किया। इस मॉक संसद में कांग्रेस सहित 19 विपक्षी दलों के 215 सांसद शामिल हुए।

मुख्यमंत्री ने 3.69 लाख तेंदूपत्ता संग्राहकों को 30 करोड़ से अधिक बोनस राशि दी



नईदुनिया प्रतिनिधि, बैतूल/भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शनिवार को बैतूल में आयोजित तेंदूपत्ता संग्राहक सम्मेलन में चार जिलों के 3.69 लाख संग्राहकों को 30 करोड़ रुपये से अधिक की बोनस राशि अंतरित की। इस अवसर पर ग्राम वन समितियों को 13 करोड़ रुपये से अधिक का काष्ठ लाभांश भी वितरित किया गया। मुख्यमंत्री ने बैतूल जिले के लिए 443 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार

बैतूल को 443 करोड़ रुपये के विकास कार्यों की सौगात

गरीब, किसान, युवा, महिलाओं और जनजातीय वर्ग के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है। प्रदेश के तेंदूपत्ता संग्राहकों को अब तक 80 करोड़ रुपये से अधिक की राशि दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि बच्चों और युवाओं को बेहतर शिक्षा तथा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। अब तक 85 हजार शासकीय पदों पर नियुक्तियों की गई हैं और एक लाख नए पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। बैतूल में जनजातीय वेटियों के

लिए 50 करोड़ रुपये की लागत से कन्या शिक्षा परिसर और छात्रावास का भूमिपूजन किया गया। कुकूरु खामला में 15 करोड़ रुपये से पर्यटन सुविधाओं का विस्तार होगा और कॉफी के बागान लगाए जाएंगे। बैतूल-मुलताई में 24 करोड़ रुपये के नए कारखाने भी स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने जिले में 50 करोड़ रुपये की नलजल योजनाओं, 15 करोड़ रुपये के गीता भवन और हाट बाजार तथा सड़क चौड़ीकरण के लिए 47 करोड़ रुपये देने की

घोषणा की। चार जलाशयों के निर्माण पर 70 करोड़ रुपये खर्च होंगे। 154 करोड़ रुपये की रामघाटी मध्यम सिंचाई परियोजना विकसित की जाएगी। चोड़ाडोंगरी में बैराज और जलाशय बनेंगे। इसके अलावा 100 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से फुटबॉल मैदान, इनडोर और आउटडोर स्टेडियम बनाए जाएंगे। बैतूल में जनजातीय संग्रहालय तथा तासी संरक्षण क्षेत्र में सफारी द्वार और तितली उद्यान भी विकसित किए जाएंगे।

पंजाब चुनाव के लिए आप की पहली सूची जारी

► जेल में बंद संजीव अरोड़ा को भी लुधियाना पश्चिम से उम्मीदवार बनाया

नईदुनिया ब्यूरो, मोहाली: पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 के लिए आम आदमी पार्टी ने 40 उम्मीदवारों को पहली सूची जारी कर दी है। इसमें मुख्यमंत्री भगवंत मान धूरी सीट से चुनाव लड़ेंगे। वर्ष 2022 में उन्होंने इस सीट पर 58 हजार से अधिक मतों से जीत दर्ज की थी। धूरी उनका

मंत्री संजीव अरोड़ा को भी लुधियाना पश्चिम से उम्मीदवार बनाया गया है। पंजाब विधानसभा का कार्यकाल मार्च 2027 में समाप्त हो रहा है। राज्य की 117 सीटों में से 94 पर फिलहाल आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान धूरी सीट से चुनाव लड़ेंगे। वर्ष 2022 में उन्होंने इस सीट पर 58 हजार से अधिक मतों से जीत दर्ज की थी। धूरी उनका

गृह क्षेत्र है। पार्टी ने संजीव अरोड़ा को लुधियाना पश्चिम से उम्मीदवार बनाया है। उन्होंने जून 2025 में इसी सीट पर उपचुनाव जीतकर मंत्री पद संभाला था। अरोड़ा कथित धनशोधन मामले में लगभग साढ़े पांच महीने से गुरुग्राम जेल में बंद हैं। पहली सूची में वित्तमंत्री हरपाल चीमा और प्रदेश अध्यक्ष अमन अरोड़ा का नाम शामिल नहीं है।

संगरूर के गांव तुरबंजारा में गुलजार की आत्महत्या के मामले को लेकर हरपाल चीमा का नाम चर्चा में रहा है। पायल सीट से विधायक मनविंदर ग्यासपुरा को फिर टिकट दिया गया है। हाल ही में श्री अकाल तख्त साहिब ने उन्हें धार्मिक सजा सुनाते हुए तनखैया करा दिया था। उन पर अकाल तख्त के जत्थेदार के बारे में अभद्र टिप्पणी करने के आरोप लगे थे।

बंगाल की खाड़ी में नया चक्रवात बनने की आशंका

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र गहरे दबाव में बदल गया है और इसके चक्रवाती तूफान का रूप लेने की आशंका है। मौसम विभाग के अनुसार, संभावित तूफान 3 नवंबर को आंध्र प्रदेश के तट से टकरा सकता है। इस दौरान हवा की गति 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने का

अनुमान है। मौसम विभाग के निदेशक मृत्युंजय महापात्र ने बताया कि तूफान के प्रभाव से तटीय क्षेत्रों में तेज हवाएं चल सकती हैं। विभाग ने आगामी दिनों में कई राय्यों में वर्षा और तेज हवाओं को लेकर चेतावनी जारी की है। इस बीच, अर्नब तूफान का असर देश के कई हिस्सों में दिखाई दे रहा है।

राजनीति

चुनाव में किसी दल को बहुमत नहीं मिलने से सरकार गठन पर गतिरोध...

इजराइल में सीधे प्रधानमंत्री चुनने की व्यवस्था पर विचार

तेल अवीव, एजेंसी: इजराइल में सरकार गठन को लेकर जारी राजनीतिक गतिरोध के बीच प्रधानमंत्री चुनने की व्यवस्था बदलने पर चर्चा शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के विरोधी दल पुरानी व्यवस्था बहाल करने पर विचार कर रहे हैं, जिसके तहत जनता संसद के सदस्यों और राजनीतिक दलों के साथ प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को भी सीधे चुन सकेगी।

27 अक्टूबर को हुए चुनाव में किसी भी गुट को बहुमत नहीं मिला। नेतन्याहू समर्थक दलों को 53 सीटें, विपक्षी गठबंधन को 48

सीटें और अरब दलों को 19 सीटें मिलीं। इजराइल की संसद में कुल 120 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए कम से कम 61 सांसदों का समर्थन आवश्यक है। विपक्ष के पास अरब दलों को शामिल करने पर 67 सीटों का समर्थन बन सकता है, लेकिन उसके कई नेता अरब दलों के सहयोग से सरकार बनाने के पक्ष में नहीं हैं। ऐसे में सरकार गठन का रास्ता कठिन हो गया है। इसी गतिरोध को दूर करने के लिए विपक्ष प्रधानमंत्री का सीधा चुनाव कराने की व्यवस्था पर विचार कर रहा है। इससे अरब दलों के समर्थन के बिना अल्पमत



सरकार बनाने की संभावना भी खुल सकती है। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए सरकार से जुड़े मूल कानून में संशोधन करना होगा। इसके लिए संसद के कम से



कम 61 सदस्यों का समर्थन जरूरी है। हालांकि, प्रस्ताव पर अभी अंतिम सहमति नहीं बनी है और इसे संसद में पेश भी नहीं किया गया है।

पहले भी तीन बार हुआ था प्रधानमंत्री का सीधा चुनाव

इजराइल में प्रधानमंत्री का सीधा चुनाव पहले भी कराया जा चुका है। 1996 और 1999 में प्रधानमंत्री तथा संसद के लिए अलग-अलग मतदान हुआ था। 2001 में केवल प्रधानमंत्री चुनने के लिए अलग चुनाव कराया गया। 1996 में बेंजामिन नेतन्याहू ने शिमोन परेज को हराकर प्रधानमंत्री पद हासिल किया था। 1999 में एहुद बराक ने नेतन्याहू को पराजित किया, जबकि 2001 में परियल शेरोन ने एहुद बराक को हराया। हालांकि, इस व्यवस्था से राजनीतिक समस्याएं पूरी तरह समाप्त नहीं हुईं। वर्ष 2001 में इसे खत्म कर इजराइल फिर संसदीय व्यवस्था पर लौट आया। नई संसद के 120 सदस्यों के 10 नवंबर को शपथ लेने की उम्मीद है। इसके बाद विपक्ष प्रस्ताव को विधेयक के रूप में पेश कर सकता है। आवश्यक समर्थन मिलने पर संसद में इस पर मतदान हो सकता है। इस बीच, चुनाव अधिकारियों और पुलिस ने चुनाव में विदेशी दखल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के आरोप को खारिज किया है। अधिकारियों के अनुसार, जांच का अंतिम चुनाव परिणाम पर असर नहीं पड़ेगा और किसी समुदाय के मत दब नहीं किए जाएंगे।